भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2017

जिसका उत्तर 17.12.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में विलंब

2017 श्री दिग्विजय सिंहः

श्रीमती फूलो देवी नेतमः

श्रीमती रंजीत रंजनः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान स्वीकृत राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में से वर्तमान में विलंबित परियोजनाओं की कुल संख्या, कुल लागत तथा प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी राजमार्ग परियोजनाओं की कुल संख्या और अनुमानित लागत कितनी है जिनकी निविदाएँ आमंत्रित एवं आवंटित की जा चुकी हैं, परन्तु जिनका निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है तथा उनका निर्माण न शुरू होने के क्या कारण हैं;

(ग) इन विलम्बित परियोजनाओं में लागत वृद्धि से बचने हेतु सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार सभी विलंबित या अनारंभित राजमार्ग परियोजनाओं को पुनः निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए क्या योजना बना रही है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान सौंपी गई 574 निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाएं जिनकी संचयी परियोजना लागत लगभग 3.60 लाख करोड़ रु. है, संविदा के अनुसार अपनी मूल पूर्णता समय सीमा से विलंबित हैं, जिनमें से 300 परियोजनाएं 1 वर्ष से कम, 253 परियोजनाएं 1-3 वर्ष की और 21 परियोजनाएं 3 वर्ष से अधिक की देरी का सामना कर रही हैं और ये परियोजनाएं पूर्णता के विभिन्न चरणों में से किसी भी चरण को प्राप्त नहीं कर पाई हैं और इनमें समाप्त किए जाने / समय से पहले बंद किए जाने वाली विचाराधीन परियोजनाएं शामिल नहीं हैं।

(ख) लगभग एक लाख करोड़ रुपये की कुल लागत वाली 133 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं सौंप दी गई हैं, लेकिन पूर्व-अपेक्षित शर्तों को पूरा करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तीय समापन की उपलब्धि और बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए संविदाकार/रियायतग्राही के साथ उपलब्ध समय अवधि

को छोड़कर वन और वन्यजीव मंजूरी सहित ऋणभार मुक्त भूमि की उपलब्धता और मंजूरी लंबित होने के कारण नियत तिथि घोषित नहीं हो पाई है।

(ग) और (घ) सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ सक्रिय सहयोग से चल रही परियोजनाओं में अवरोधों/बाधाओं की समीक्षा और समाधान के कार्य तंत्र का सदुपयोग करने हेतु भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। नई परियोजनाओं के लिए आवश्यक मंजूरी/अनुमोदन की उपलब्धता और पूर्व शर्तों की पूर्ति में तेजी लाने के लिए भी पूर्ण प्रयास किए हैं।

उपरोक्त के परिणामस्वरूप, 3 वर्ष से अधिक की विलंब वाली परियोजनाओं की संख्या दिनांक 01.04.2024 को 152 से घटकर दिनांक 30.11.2025 को 85 रह गई है। इसके अतिरिक्त, जिन परियोजनाओं के लिए नियत तिथि 12 माह से अधिक समय तक प्रदान किए जाने के बाद भी घोषित नहीं की जा सकी, उनकी संख्या दिनांक 01.04.2024 को 87 से घटकर दिनांक 30.11.2025 को 45 रह गई है।

*****